राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ भारत क्षेत्र-IV का दिनांक 23 सितम्बर, 2018 को माननीय अध्यक्ष हि0 प्र0 विधान सभा डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित हुए सम्मलेन एवं कार्यशाला की कार्यवाही।

*****

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : Conference of Presiding Officers of Legislative Bodies and Workshop for the Members of Zone-IV CPA India Region, के द्वितीय दिवस पर मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनन्दन करता हूं, स्वागत करता हूं। कृपया आप सभी अपने-अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखें, अगर इसको बुक की तरह फोल्ड करके जब आगे ले जाएंगे तो यह किताब के पन्ने की तरह पलटेगा और इसमें आप देखेंगे कि पहले नम्बर पर आएगा। Workshop for Member of Zone-IV CPA India Region का टाइम शैड्यूल हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है।

आज की इस कार्यशाला में पधारे आप सभी महानुभावों का हिमाचल प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनन्दन करते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। 22 सितम्बर, 2018 इस विधान सभा में एक ऐतिहासिक दिन रहा, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी की अध्यक्षता में जो यह वर्कशॉप और सी0पी0ए0 कान्फ्रेंस सम्पन्न हुई वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई है जिसमें आप लोगों की भागीदारी हमारे लिए तथा सबके लिए प्रेरणादायी रही है। हमने पिछले कल दो विषयों को पूरी तरह कनक्लूड किया जिसके अंतर्गत 'One Nation One Election' के ऊपर चर्चा हुई। यह विषय ऐक्ट अपॉन करने का नहीं था बल्कि जन-मानस में एक विचार प्रवाह को तेज करने का था। दूसरा विषय 'नशा मुक्त समाज' था जिसके अंतर्गत सभी ने एक स्वर से नशे को समाप्त करने की बात के ऊपर संकल्प लिया।

कल इन दो विषयों, e-Vidhan/ e- Constituency Management और National e-Vidhan Application (NeVA) की शुरुआत हुई, आज हम इन दो विषयों के ऊपर गहनता से अध्ययन करते हुए अपने ज्ञानवर्धन का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में हम आधे घंटे के लिए जिसमें 15 से 20 मिनट सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अपने 'NeVA' (National e-Vidhan Application) विषय को रखेंगे। उसके बाद श्री धर्मेश शर्मा जी, निदेशक (IT) हि0प्र0 विधान सभा, e-Vidhan और e-Constituency Management के ऊपर 15 से 20 मिनट तक अपना विषय रखेंगे और दोनों विषयों के ऊपर प्रश्न-उत्तर सैशन 15 से 20 मिनट का रहेगा। अतः मैं सीधे-सीधे सचिव (भारत सरकार) पार्लियामैंटरी अफेयर्स से चाहूंगा कि आप अपना विषय प्रस्तुत करें। आप अपना विषय अपनी सीट पर बैठे-बैठे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकारः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अतिथिगण, सम्मानीय अध्यक्ष महोदयगण; एक प्रिविलैज की बात है कि आज मुझे एक बार पुनः National e-Vidhan application (NeVA) विषय के ऊपर महानुभावों को कुछ बताने का सौभाग्य मिला है। National e-Vidhan application (NeVA) में वे सारी चीजें हैं जो अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताई है। ऐसी डिवाईस अगर आप अपने हाउस में लगाते हैं तो नेशनल ई-विधान का जो डेटा है वह आपके हाउस में इसी तरह, इसी माहौल में तथा इसी फोरमैट में दिखेगा। I am making it very clear that National e-Vidhan Application (NeVA) is an upgradation of all that has been done in Himachal Pradesh. It is not substitution of e-Vidhan Application of Himachal.

दूसरी बात यह है कि अभी तक हमने राष्ट्रीय स्तर पर इन-हाउस आटोमेशन को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इसका अर्थ यह है कि जब माननीय सदस्यगण हाउस के अंदर आते हैं तो उनको क्या-क्या चीजें चाहिए और वे सारी चीजें इनस्टैंटली मिल सकती है या नहीं। हमने आज जो ऐप्लिकेशन बनाया है उनमें जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको जो 6-7 चीजें चाहिए वे इनस्टैंटली मिलेगी तथा वे उसी तरह से मिलेगी जिस तरह

से हिमाचल प्रदेश में माननीय विधायकों को मिलती है। इसमें जो भिन्नता है उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप सुबह सबसे पहले लिस्ट ऑफ बिजनैस खोलते हैं। हमने लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों से इस बारे में बातचीत की है और उनका कहना है कि हमें लिस्ट ऑफ बिजनैस जरूर चाहिए बाकी सब चीजें तो हम सदन में पहुंचने पर ले लेते हैं। इसलिए हमारा पहला स्टैप यह है कि आपके मोबाइल पर लिस्ट ऑफ बिजनैस कैसे मिल सकती है और लिस्ट ऑफ बिजनैस बनाने का जो डेटा प्रोसैस है उसके लिए सचिवालय के लोगों को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जायेगी। Current List of Business is nothing but a schedule of Business to be held in the House which consists of many other sub setup information.

लिस्ट ऑफ बिजनेस में ऑबिच्यूरी से लेकर जितनी भी कार्यवाही होती है, वह सब पहले से मैंशन होती है। जिसको माननीय अध्यक्ष की अनुमति से माननीय सदस्यगण उपयोग करते हैं। List of Business is the first thing that we deliver through NeVA and delivers in the same and similar manner. In the House you can see it on your laptops and I-pads. So it is a short method without going into the H.P. model or any other model. I am saying this because every House has different level of automation. Every House and every Hon'ble Member will get all the information which the e-Vidhan in Himachal Pradesh is providing in a touch screen device, which is called I-pad, and obviously on phone also. Perhaps everything will be available in e-Vidhan.

Second point is 'Papers to be Laid' हमने लोक सभा और राज्य सभा में देखा है कि 'Papers to be Laid' में लिस्ट ऑफ बिजनेस में लिखा होता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अब माननीय मंत्री अपने मंत्रालय के विषय में एक रिपोर्ट हिन्दी व अंग्रेजी में प्रस्तुत करेंगे। इसकी जो कॉपियां होती है, वह सचिवालय के पास होती है और ये कॉपियां माननीय सदस्यों के पास या तो बाद में पहुंचती है या कभी नहीं पहुंचती है और जब पहुंचती है, तब तक उनको एक और रिपोर्ट उसी विभाग की मिल चुकी होती है। इसलिए माननीय सदस्य कभी भी अद्यतन नहीं रहते हैं। हमने कोशिश की है कि when the Hon'ble Member is laying a paper, the concerned paper is attached and is

open-able in the device that you are carrying in your hands. So, we are attaching that report in the PDF format in the Booklet. The same is placed when the Hon'ble Member rises to lay a report of his/her Department or Ministry on the Table of the House. You can browse it instantly. The beauty is that this report has to be uploaded by the Department itself. It is not done by the Secretariat. सचिवालय का काम है, अपनी रिपोर्ट्स को देना जैसे वे लोग क्वैश्चन का आंसर देते हैं। क्वैश्चन का आंसार और पेपर लेड, ये दोनों काम विभाग करते हैं, उनको भी इसमें यूजर आई0डी0 और पासवर्ड हैं। जब माननीय मंत्री कागजात सभा पटल पर रख देते हैं तो it becomes accessible to the Hon'ble Members.

Third thing is the Bills. मुझे हिमाचल प्रदेश विधान सभा के बारे में बहुत कम ज्ञान है लेकिन लोक सभा और राज्य सभा में माननीय सदस्यों को बिल की कॉपी 24 घण्टे पहले मिलनी चाहिए। When the Bills are being introduced the same are made available for consideration and passing the moment the Hon'ble Speaker allows the Hon'ble Member or the Hon'ble Ministers to introduce the Bill. Suppose I rise to lay the Bill number XYZ on the Table of the House, the copy of the XYZ Bill for introduction in the same format is uploaded and available to all the Hon'ble Members inside the House; to all the members of media and Press; and everywhere globally at the same time. House is the most transparent body under the Sun where everything is available to everybody at the same time.

Similarly, the Committee Reports are presented in the House before the introduction of the Bills. Sometimes the Committee Reports are bulky and unwired. Many a times the Reports have so many "Annexures" and in that case nobody reads the main report. I have full respect to the Committees but Committee Reports are generally not available in time. The Committees of the House submit its report prepared by the Secretariat. Sometimes the Committee Members from the Lok Sabha and Rajya Sabha are common also. So one Member of the Committee presents the report and that report is not available generally until it is signed by the Chairman of the Committee. So the

most authentic copy is generally not available. Sir, what I am only trying to convince is that the report which is supposed to be presented by the Committee is also instantly uploaded by the House. In this case the Secretariat uploads the report. The moment the House uploads the copy, one copy is made available to everybody as part of List of Business and it is the event as it happens.

The fourth and most important part of this is 'Question and Answer'. Under question category we put Starred and Unstarred Questions separately. The Starred Questions and their relevant replies are attached to it immediately. There are two types i.e. if one wants to read the question, the question will be available and if one wants to read the reply, the reply will be available. One thing which the Himachal Pradesh has done little ahead of us is that when the Hon'ble Minister answers the question, the bureaucracy supplies more information to the Hon'ble Minister. But we don't want to do it countrywide. In Government of India, we call it notepad and here we call it briefing. Here in case of Himachal Pradesh they have allowed the briefing to be attached along with the Question but that is accessible only to the Hon'ble Minister and not to the Hon'ble Members. In our case we have deliberately taken a decision that in public domain this portion we will be omitting because the Hon'ble Minister knows more information and generally bureaucracy briefs him some different point of view most of the time. Many times the bureaucracy briefs on various non-administrative angles (who has asked the questions and why the question has been asked, what has been our previous stand and what has been our revised stand, all those features are there). The notepad and briefing portion will not be available in NeVA. If the Hon'ble Member wants we can make it available.

Dr. Rajeev Bindal, Hon'ble Speaker, H.P. Vidhan Sabha: In Himachal Pradesh also it is not available to the common man.

Shri Surendra Nath Tripathi, Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs (GOI): It means it is only accessible to theHon'ble Minister.

Dr. Rajeev Bindal, Hon'ble Speaker, H.P. Vidhan Sabha: It is the property of the Minister and when supplementary is asked then he can reply from that notepad which is the property of the House.

Shri Surendra Nath Tripathi, Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs (GOI): Okay, Sir. It becomes the verbatim and that is the part of records. The Starred Questions are listed first, soon after that you go to the next column you will get Unstarred Questions. In Lok Sabha we have only 15 Starred Questions but 160 Unstarred Questions every day. These 160 Unstarred Questions which are laid on the Table and in the Lok Sabha, one copy is given to the Member who has put the question and rest 70 copies are put on the Table of the House. So in the House of 600 Members, I don't know why they have decided it that as if nobody else is interested in these questions. In NeVA model we have tried to say that every question whether you have asked or not, starred or Unstarred, every Member and every citizens of this country will get reply instantly. The authentic reply will be made available to you. As Hon'ble Speaker Himachal Pradesh was saying that there is a supplementary portion, supplementary portion is when a question is asked that becomes the Business of the House for the day. When it becomes part of verbatim or becomes part of synopsis it becomes part of the House Proceedings that will be made available to the Members next day before opening of the House. Under Bulletin Part-I & II, Bulletin Part-I is a generally scheduled that how the time is spent of the House and Bulletin-II is generally the notices being issued to the Hon'ble Members. That is the traditional in Lok Sabha and Rajya Sabha. Generally one Bulletin-I is issued every day.

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा: माननीय कंवर पाल जी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा विधान सभा यहां पर आए हैं। मैं इनको बताना

चाहूंगा कि अभी यहां पर जिस विषय के ऊपर वार्ता शुरू हुई है, वह "लोकसभा में National e-Vidhan Application (NeVA) है और यह आपकी स्क्रीन के ऊपर उपलब्ध है।

Shri Surendra Nath Tripathi, Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs (GOI): सर, जब माननीय सदस्य सदन के अंदर आते हैं तो उन्हें लिस्ट ऑफ बिजनैस और जो कागजात सभा पटल पर उपस्थापित किये जाने होते हैं आदि सूचियों की आवश्यकता रहती है। उन्हें उन कागजात की एक कॉपी की आवश्यकता भी रहती है। इतना ही नहीं जो Bills विचाराधीन होते हैं या जो विचार-विमर्श उपरान्त पारित किये जाने होते हैं, कमेटीज़ की रिपोर्ट्स, चाहे वह हाउस कमेटी हो , ज्वाईंट कमेटी हो, कंसलटेटिव कमेटी हो या अन्य कोई भी कमेटी हो, उन कमेटियों की रिपोर्ट्स कौन प्रस्तुत करेंगे और उस कमेटी की एक्चुअल अथैंटिक रिपोर्ट्स इत्यादि इन सब कागज़ात की आवश्यकता भी उन्हें रहती है। Similarly, questions and answers - both starred and un-starred - are listed. Similarly, Bulletin Part - I, which is the time schedule of yesterday meetings of the House, and Bulletin Part - II, which is the day-to-day and time to time instructions being given to the Hon'ble Members, is also be made available to the mobile sets of the Hon'ble Members. We are also uploading the synopsis of the proceedings.

Dr. Rajeev Bindal, Hon'ble Speaker, H.P. Vidhan Sabha: At what time Bulletin is being released on the NeVA?

Shri Surendra Nath Tripathi, Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs (GOI): Sir, NeVA is not my application. NeVA is supposed to be uploaded by the staff of the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

Dr. Rajeev Bindal, Hon'ble Speaker, H.P. Vidhan Sabha: At what time they upload it?

Shri Surendra Nath Tripathi, Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs (GOI): They upload it as it happens. In Lok Sabha synopsis and bulletin are supposed to be uploaded every hour. They issue so many bulletins every day, especially Bulletin Part - II. Bulletin Part - I - synopsis as well as synopsis of the proceedings - is released before the House meets, in fact close of the day. There are many issues like typing, verbatim and error corrections. They are putting all the three versions online immediately and we try to accommodate all those things into the House as well as into this NeVA application also.

Sir, this is the scenario why we have thought of National e-Vidhan Application. Both the Houses of Parliament (Lok Sabha & Rajay Sabha), 31 Assemblies, 7 Councils and 40 Houses are there in India. Each year we handle over 2.00 lac questions and their answers, both starred and un-starred taken together; about 2000 Committee Reports are available; and over one lac papers are laid in different Houses and many times they are laid in different languages. This entire set of information will be available to every Member of the Parliament and Assembly through NeVA. We are not saying that we are trying to interfere in the House. We have no such intention. But the Hon'ble Member is entitled to the reply which is being given on the same subject, may be by Lok Sabha or a Minister in the Lok Sabha; may be by a Minister in the Rajya Sabha; may be any other Minister in any other Assembly; and all those things are available to you in your mobile as well as tablet which is the plus of e-Vidhan of Himachal. In Himachal, obviously you will get only the information relating to this historic august House but you will not be able to get the information of any other House. Even if you adopt the Himachal model in your own system, you will only get your own information in the House. In NeVA we have tried to give this information of all the Houses who come on board on NeVA because information is then asset. This is the age of information. Everybody has become consumer of information, but the authentic content is created only in the Lok Sabha, Rajya Sabha and Vidhan Sabhas. There is no better place in this part of democratic world where most

authentic information is given. So that information is made available to all of you, Sir, seamlessly for two lac questions and so on and so forth.

Yesterday, I was telling, Sir, the beauty of Himachal is that you need a touch screen device inside the House which is very beautifully located/ placed and look and feel is also that of a book but you cannot carry this device. If you carry, this will be a theft. I don't know that the Hon'ble Speaker can ignore one time one can carry on. What we have tried to do is we will put this device also in the House so that the information is accessible to you on this device and on top of it the same information in a similar undiluted manner for any country for any House is available to you in your mobile, desktop at your House and tablet which you may carry. In Lok Sabha and Rajya Sabha we have provided tablet out of Government cost. So this is the beauty of NeVA that not only in House you need but you also need to access it seamlessly. There is no need for further training like here this touch screen enabled in Himachal Pradesh - I am not criticising because this is not my business also - this is available in window screen. Window touch screen devices are now virtually going to be extinct species. Now the android is dominating the world with 92 per cent share of market and 7 per cent is available to the apple which is high-end devices. Microsoft enabled touch screen devices are very rare unless you are very much committed to this device. What we have enabled that you can get in the state of art technology in your touch screen devices.

I will request the Hon'ble Members to download NeVA so that we can travel alongwith you. It may take 5 minutes, Sir. It will really be a good experience. Here in this House the WiFi is available. I can request the Hon'ble Speakers to open their respective devices and download NeVA application on it right now. In case of difficulty, the staff present here can assist you. Here in this House very high speed WiFi is available. The user ID of the same is House 1 and House 2 and the password is 99999999.

(Request was made to the officers of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha e-Vidhan to assist the Hon'ble Speakers and Hon'ble Members to connect the WiFi on their respective mobiles)

In fact the scheme which we are thought of we will buy 10000 tablets and provide the same to you as and when the scheme is approved. I will answer all those questions which are relevant. At the moment, the Hon'ble Members have their devices with them and the same are very-very commonly available.

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभाः कुछ माननीय सदस्य चाह रहे हैं कि अगर हिन्दी में इस विषय पर बता दें तो अच्छा रहेगा। क्या सभी माननीय सदस्यों ने इंस्टोल कर लिया है?

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार : सर, इसके होम स्क्रीन में जो दिख रहा है और जैसा कि इसके पावर प्वांइट पर लोकसभा, राज्य सभा, विधान सभा और विधान परिषद दिखाया है। जैसे ही आप लोक सभा पर क्लिक करेगें तो लोक सभा की साइट निकल जाएगी। The smartness level of Himachal is visible here.

सर, इसमें माननीय विधान सभा अध्यक्ष का डाटा है। सर, इसमें गुजरात का डाटा भी आएगा। इस पर हर हाउस का डाटा उपलब्ध है। सर, 40 हाउसिज का डाटा इसमें उपलब्ध है। जितना हम अपने लेवल पर कर सकते थे, उतनी इंफॉर्मेशन इसमें उपलब्ध हैं। सर, इसमें यदि आप पंजाब, विधान सभा को देखेंगे तो पंजाब, विधान सभा के सारे सदस्यों की बहुत ही खूबसूरत फोटो दिख रही है। The quality of picture is very good.

Sir, this is available in your pocket and in devices. When you open the House उसमें सबसे पहले माननीय अध्यक्ष का फोटो दिखेगा। हमने हाउस के होम पेज़ पर स्पीकर का फोटो लगा रखा है। यदि कहीं से रिक्वेस्ट आएगी तो मुख्य मंत्री या राज्यपाल का फोटो भी लगाया जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने अभी अध्यक्ष का ही फोटो लगा रखा है। Because in the House the Hon'ble Speaker is the King and his photograph should be there. इसमें एक ब्लू डॉट है अगर उसको क्लिक करेंगे तो

इसमें सदन के माननीय सदस्यों की लिस्ट और उनके फोटोग्राफ्स आ जाएंगे। जब मैंबर अपने फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे तो उनका फोटो दिख जाएगा। We will give a false sense as if it is designed for them but it is the only system the photograph of all and everybody is there.

Sir, I want to thank you for giving me this opportunity. If there are any questions I will be happy to answer them.

Shri Dushyantbhai Rajnikant Patel, Hon'ble Member, Gujrat Vidhan Sabha: Firstly, there are some information which needs to be kept secret within the Parties. When Minister is giving the answer, some information is to be kept secret within the Parties. What is the solution for this? Secondly, the Minister should keep the positive answers, उसके पास जो पोजिटीव उत्तर होते हैं वह उसके पास रखने चाहिए। This portion cannot be reflected in the answer. What is the solution for this?

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार: हमने वर्तमान स्थिति में माननीय मंत्री जी का जो फोल्डर पोंशन है, उसको इससे दूर रखा है। इसमें हाउस को जो रिप्लाइज प्लेस कर रहे हैं, हम उसी को दिखा रहे हैं। In fact House never sees what is in the folder of the Hon'ble Minister and that is not the property of the House. It cannot be disclosed to any other Member. That is the privilege of the Hon'ble Minister and we are not interfering in that. I think it is clear.

श्री दुष्यंतभाई रजनीकांत पटेल, माननीय सदस्य, गुजरात विधान सभा: मुझे एक और बात पूछनी है। जब माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं तो उसके बाद माननीय मंत्री जी उत्तर देते हैं। ऑपोजिशन वाले यह पूछ सकते हैं कि जो मैंने प्रश्न पूछा हुआ है उसका जो जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे हैं वह ई-विधान में रिफ्लेक्ट नहीं किया है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं या ऐसा हो सकता है?

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकारः सर, ऐसा नहीं हो सकता है।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : मैं प्रैक्टिकली बता देता हूं। जो मंत्री महोदय के पास सूचना है, उनके पास पूर्ण सूचना है क्योंकि वे इस लेवल तक तैयार होकर आते हैं कि सामने वाला क्या सप्लीमेन्टरी क्वैश्चन पूछ लेगा, इसका क्या पता है। तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, वे सारे तैयार करके लाते हैं। परन्तु हमारे रिकॉर्ड में चाहे वह ई-विधान हो या हार्ड कॉपी हो, उसमें केवल वही उत्तर जाएगा जो रिप्लाईड है। चाहे वह इसमें रिपलाई किया है या सप्लीमेन्टरी में रिप्लाई किया है। बाकी सब मंत्री जी की प्रॉपर्टी है।

श्री दुष्यंतभाई रजनीकांत पटेल, माननीय सदस्य, गुजरात विधान सभा : उस केस में जैसे नंबर भी है कि कितनों को लाभ दिया और उसका उत्तर आया 5,000, और कभी उत्तर उससे विपरीत या अलग होता है। कई बार जो उत्तर हमें पेपर में मिलते हैं, जैसे कि किसी गरीब को किसी योजना के अन्तर्गत कितना लाभ दिया? उसका जवाब अलग होता है। और फिर प्रश्न-उत्तर में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जिसका मंत्री जी जवाब देते हैं। इसमें भी विपक्ष वाले बोलते हैं कि जितना आपने हमको अभी जवाब दिया, अगर वही प्रश्न के लिखित उत्तर में पूरा रिफलैक्ट कर दिया होता तो इसमें यह दूसरा प्रश्न खड़ा ही नहीं होता।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : नहीं, यह तो मंत्री जी की इन्टेलीजैन्स है कि वह प्रश्न के अनुसार उत्तर कैसे देते हैं और वह अनुपूरक प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देते हैं। परन्तु जो फिगर्ज विधान सभा में दी गई हैं, वे ऐक्चुअल फिगर्ज से वैरी नहीं कर सकती हैं, it is 'Contempt of the House' and contempt proceedings can be made against the Hon'ble Minister.

श्रीमती गीता भुक्कल, माननीय सदस्य, हरियाणा विधान सभा : इसमें जैसा आपने कहा कि मंत्री जी के पास सारी सूचना है। कई बार मंत्री जी को जो उत्तर देना है, जो notepad पर होता है। It is right that the Ministers should be well equipped, लेकिन हमारे

यहां इतना बड़ा सेट-अप नहीं है because already we are dependent on Principal Secretaries, Directors and the other staff members. If we have to work on e-paper, we have to do all the things ourselves. तो क्या मंत्री जी हमारे ई-विधान के हिसाब से इतने कैपेबल हैं कि जैसा उन्होंने कोई सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछा तो तुरन्त क्या अपने आप भी सर्च ऑऊट करेंगे? क्योंकि ultimately we have to give reply from our own mind और अपने दिमाग से ही हमने इस आर्टिफिशियल माइन्ड को चलाना है जोकि ई-गवर्नैन्स या जो हमारा ई-पेपर है। My question is that we are dependent on the Secretaries and the supporting staff. इतना प्रशिक्षण खास तौर से हिमाचल प्रदेश विधान सभा में हो चुका है कि जो मंत्री महोदय उत्तर देंगे या जो विधायक प्रश्न करेंगे, वे सारे-के-सारे प्रश्न और उत्तर उसी समय उपलब्ध होंगे या कुछ सपलीमेंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिसमें मंत्री जी बहुत ज्यादा अपडेट नहीं होते। लेकिन उनका उत्तर विधान सभा की कार्यवाही में आएगा। तो मेरा प्रश्न यह है कि ई-पेपर के बारे में किस प्रकार की तैयारियां माननीय विधायक महोदय द्वारा या माननीय मंत्री द्वारा या फिर जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से रहती हैं?

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : प्रैक्टिल रिप्लाई, ऐसा है कि आप 100% सही बोल रही हैं कि मंत्री जी को उतनी आई.टी. की जानकारी नहीं है जो पूरी तरह अपनी टेब चलाकर वह देख लें। कुछ लोग हैं जो टेब के ऊपर टोटल अन्सर लेकर आते हैं, परन्तु उनकी हार्ड कॉपी उनके साथ उनकी टेबल पर रहती है। वह लेकर आते हैं। अभी तक यह स्थिति है और आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी ऐक्सपर्टीज बढ़ जाएं क्योंकि विधान सभा में तो उनको असीस्टैंस नहीं मिलेगा। विधान सभा में तो उनको अकेले ही उत्तर देना है। इसलिए वे हार्ड कॉपी अभी तक साथ में रखते हैं।

श्री रणबीर सिंह पठानिया, माननीय सदस्य, जम्मू-काश्मीर विधान सभा : मान लो किसी दिन प्रश्नकाल के लिए 30 या 15-20 सवाल शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो उसमें हमेशा यह इशु रहता है कि पहले 2-4 या 5 सवालों को टाईम ज्यादा मिल जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि जो टेल एन्ड वाले हैं उनका नंबर ही नहीं आता है। कभी डिस्टरैप्शन हो जाता है और कभी एक सवाल ही इतना लंबा हो जाता है कि तब तक प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है। तो क्या ई-विधान में हम ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें एक फेयर तरीके से बैलेट हो पाए। मुझे लगता है कि असैम्बली स्टाफ के ऊपर भी इसमें निर्भरता हो जाती है

कि जैसे किसी मंत्री महोदय को कोई सवाल पसन्द नहीं है तो वे बोल देंगे कि इस सवाल को देर से लगा देना। ऐसा न हो, क्या इसके लिए हम कोई एप्लीकेशन विकसित कर सकते हैं जिससे प्रौपर तरीके से ये व्यवस्था हो जाए?

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : आपके दो सवाल अलग-अलग हो गए हैं। मैं सर्वप्रथम आपके दूसरे सवाल की बात करता हूं। सदन में किसी सवाल को प्रेफरेंस देने का प्रावधान नहीं रहता है। जो हम ई-मेल से प्रश्न भेजते हैं वे हमारे यहां पर with time रजिस्टर्ड होते हैं यानी उन प्रश्नों की तारीख और समय रजिस्टर पर अंकित होता है। जो 14 तारीख को प्रश्न एंटर हुआ, उसका रिप्लाई पहले आएगा और जो 15 तारीख को प्रश्न एंटर होगा, उसका रिप्लाई बाद में आएगा। हां, इतना तो हो सकता है जो आपने पहला प्रश्न किया कि 15 प्रश्न लगे हैं और 15 प्रश्नों में पहले नम्बर पर कौन सा लगा और दूसरे नम्बर पर कौन सा लगा। इसको हम नहीं कह सकते कि ऐसा कहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है परन्तु वह भी टाइम शैड्यूल से ही चलता है। अगर हम पूरी तरह उसको एडेयर करें तो यह समस्या भी खत्म हो जाती है क्योंकि प्रश्न आपने ऑनलाइन भेजे हैं। परन्तु जिसने हार्ड कॉपी दी है तो उस प्रश्न को जिस समय रिसीव किया, उसका समय और तारीख दर्ज़ करते हैं और उसको वहीं पर ऑनलाइन एंटर किया जाता है। वहां हमारा कोई कर्मचारी बैठा होता है। जैसे ऑफलाइन मैंने 15 प्रश्न आज डाल दिए तो ऑफलाइन डालते ही वहां पर जो व्यक्ति बैठा है वह उसको अपलोड करेगा क्योंकि ऑफलाइन वह जाएगा ही नहीं और ऑनलाइन उसको चढ़ाना ही पड़ेगा। उसको हमारा विधान सभा का स्टाफ चढ़ाएगा।

श्री रनबीर सिंह पठानिया, माननीय विधायक, जम्मू-कश्मीर विधान सभा : अगर कोई क्वायरी आ जाए तो क्या उसका डाटा ई-विधान में उपलब्ध होता है?

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : अगर क्वायरी आती है तो विधान सभा अध्यक्ष के चैम्बर में आकर माननीय सदस्य को कन्फरमेशन देते हैं। हम सदन में कन्फरमेशन नहीं देते हैं। हम उनको पूरा रिकॉर्ड दिखाते हैं कि ये देखो फलां तारीख को इतने समय में आपका प्रश्न आया है। हमारे एक माननीय विधायक ने इसी सत्र में प्रश्न उठाया कि मैंने 8 प्रश्न भेजे और मेरा एक भी प्रश्न नहीं लगा। हमने लिखित में सारी

डिटेल उनको उपलब्ध करवा दी कि फलां दिन में इतने समय में आपका प्रश्न आया और आपने अनस्टार्ड फॉर्म के ऊपर सारे-के-सारे प्रश्न लिख दिए तो वे स्टार्ड में कैसे अपीयर होने थे? तो कमी वहीं पर नज़र आ गई क्योंकि माननीय सदस्य की ओर से कमी थी। तो ऐसे प्रावधान हैं।

जो प्रश्न आपने सबसे पहले पूछा उसका न तो कोई "नेवा" के पास आंसर है और न हमारे पास कोई आंसर है। अब तीन प्रश्नों के ऊपर चर्चा होगी या 30 के ऊपर चर्चा होगी, इस बात को या तो अध्यक्ष जान सकते हैं या सदन जानें।

श्री रनबीर सिंह पठानिया, माननीय विधायक, जम्मू-कश्मीर विधान सभा : यह बैलेट का प्रावधान जैसे गुजरात से आए प्रतिनिधि कह रहे हैं कि इनके यहां है जबकि हमारी विधान सभा में नहीं है और लोक सभा में भी यह सिस्टम है।

श्री राजेन्द्र सूर्यप्रसाद त्रिवेदी, अध्यक्ष, गुजरात विधान सभा : जैसे 1500 प्रश्न आ गए तो 1500 प्रश्नों का बैलेट होगा और वह पूरा नम्बरिंग में जाएगा। जब सदन में प्रश्न काल होगा तो जिसका नम्बर पहला आया है तो वह अपना पहला सवाल पूछेगा और हमारे यहां एक घण्टे का प्रश्न काल होता है और उस एक घण्टे में कई बार 20 प्रश्न कवर हो जाते हैं और कभी 4 प्रश्न में ही प्रश्न काल समाप्त हो जाता है।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : मुझे लगता है कि जो ई-विधान एप्लीकेशन है उसके संबंध में क्वायरीज नहीं हैं। ये other क्वायरीज हैं।
मुझे लगता है कि अब अगला विषय ले सकते हैं। हम चाहेंगे कि ई-कन्स्टीच्यूएंसी मैनेजमैंट के ऊपर निर्देशक(आई0टी0) हिमाचल प्रदेश विधान सभा, श्री धर्मेश शर्मा जी अपनी बात रखें। यह बिल्कुल नई चीज है और इसका हम भी अभी ट्रायल ही कर रहे हैं। इसमें आगे कैसे कामयाबी मिल सकती है, इसको देखने का प्रयास करेंगे।

श्री धर्मेश शर्मा, निर्देशक(आई0टी0) हि0 प्र0 विधान सभा : माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा, अन्य राज्यों से आए विधान सभा के माननीय अध्यक्षगण एवं अन्य माननीय विधायकगण। मैं आज ई-कन्स्टीच्यूएंसी मैनेजमैंट पर आपको सिस्टम के बारे में एक प्रेजेंटेशन यहां पर देना चाहता हूं। ई-कन्स्टीच्यूएंसी मैनेजमैंट सिस्टम के माध्यम से माननीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यों एवं उनके द्वारा विभिन्न

विभागों को भेजे गए पत्रों की समीक्षा कर सकते हैं। e-Constituency Management System के माध्यम से माननीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सभी कार्यों एवं उनके द्वारा विभिन्न विभागों को भेजे गए पत्रों की समीक्षा कर सकते हैं। e-Constituency mobile app और web Application द्धारा माननीय विधायकों को Constituency level पर Departmental heads के साथ Connect किया है।

e-Constituency Management एक ऐसा Programme नही है जो किसी state level और एक स्थान से एक बार मे ही launch कर दिया जा सके। इसके लिए विधान सभा ने निर्वाचन क्षेत्र मे जाकर वहां के विधायक और विभागाध्यक्षो के लिए training cum workshops आयोजित की है ताकि सभी कार्यालय सुचारू रूप से माननीय विधायक को online update कर सके। अभी तक 18 Constituency के लिए जिला एवं उपमण्डल स्तर पर Training- cum workshops आयोजित की गई है जिनको अधिकतर माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने Preside over किया है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यह वर्कशॉप डिस्ट्रिक्ट लैवल में, सब डिविजन लैवल में की गई हैं। माननीय अध्यक्ष जी वहां पर रहे हैं। वहां पर प्रश्न भी आएं हैं। उनका पूरा रिप्लाई भी किया है। पूरे प्रेजन्टेशन के माध्यम से वहां पर समझाया गया है। सबसे पहले इस तरह की workshop की शुरूआत माननीय अध्यक्ष महोदय की Nahan Constituency से की गई है। उनके बाद माननीय मुख्यमन्त्री की Constituency को लिया गया । इस तरह 18 Constituencies में e-Constituency Management का कार्य पूरा हो चुका है।

माननीय विधायकों को हर तरह के किए जा रहे कार्यों का status जैसे कार्य कब sanctioned हुआ तथा कितना पैसा खर्च हुआ और उसकी फोटो ग्राफ सहित फिजिकल Progress Constituency level पर हर Departmental head अपडेट करते है।''

इसके अलावा माननीय विधायक जो भी पत्र विभिन्न विभागों को भेजते हैं, उसका Action taken हर Department माननीय विधायक को online e-Constituency app के माध्यम से update करते हैं। इसमे ना केवल Constituency level के Departmental heads को connect किया जाता है, जैसे आप सामने स्क्रीन में देखेंगे कि इसमें माननीय विधायक ऊपर हैं और बीच में अभी तीन इनिशियल लैवल पर फंक्शनल्टीज़ स्टार्ट की गई है कि इसमें किसी भी तरह का वर्क्स, चाहे वह एम0एल0ए0 लेड से रिलेटिड हो या और

किसी भी तरह का कार्य हो उसका स्टेट्स उनके मोबाइल पर रहता है। उनके चुनाव क्षेत्र में वेकैंसी पोजिशन और जो भी पत्र उन्होंने लिखे हैं, उनको वहां पर अपडेट करके उनका स्टेट्स मोबाइल पर रहता है। हम उसको भी आपको बताएंगे कि यहां पर वह किस लैवल तक पहुंच चुका है। इस लैवल में Constituency के जो डिपार्टमैंटल हैड्ज हैं, उनको तो कनैक्ट किया, उसके साथ-साथ राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो हमने अभी तक DC और SP office को online connect कर दिया है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लैवल में भी काफी पत्र माननीय विधायक लिखते हैं। इसके बाद Next level में Hon'ble Ministers और State level officers को भी e-Constituency Management से जोड़ दिया जाएगा ताकि माननीय विधायक को हर जानकारी अपने मोबाईल के माध्यम से मिल सके और अपने निर्वाचन क्षेत्र की हर तरह की Activity की आनलाइन समीक्षा कर सके । अभी हमने स्टेट लैवल पर माननीय विधायकों को इसलिए कनैक्ट नहीं किया है क्योंकि पहले हर Constituency में जा करके सभी को उसके बारे में बताया जाएगा। जब यह पूरा डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे नहीं तो यह कन्फ्युज़न इनिशियल लैवल पर हो सकता है। माननीय विधायक e-Constituency mobile app जब अपने mobile पर open करते है। अभी आपने NeVA Apps को डाउन-लोड किया वहीं पर ही e-Vidhan से रिलेटिड जो एच0पी0ए0 की Mobile Apps हैं, वहां पर आपको तीन Mobile Apps मिलेंगी। नेशनल नेवा के साथ-साथ उसमें एक असैम्बली से रिलेटिड है। असैम्बली से रिलेटिड सारा कार्य उसके अन्दर mobile app पर रहता है। दूसरी e-Constituency mobile app है। तीसरी पब्लिक के लिए है My MLA mobile app. तीनों को अलग-अलग फंक्शनल्टी के हिसाब से, उसकी सिक्रेसी मेंटेन करने के हिसाब से अलग रखा गया है। जैसे ई-असैम्बली में यह बात आई कि जो माननीय मंत्री जी हैं उनके सप्लीमैंटरी रिप्लाईज़ यहां (Touch Screen Laptop) उपलब्ध नहीं रहते हैं। लेकिन उनके जो पर्सनल मोबाईलज़ हैं, जब वे इसे खोलेंगे तो वह इंफोरमेशन उपलब्ध रहती है। इससे यह होगा कि कोई सप्लीमैंटरी क्वैश्चन पूछे तो उनको कागज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा।

e-Constituency Management' की ऐप है। इसमें बहुत सारी ऑप्शन्ज़ हैं जैसे पब्लिक वर्कस, एम0एल0ए0 डायरी और वैकेंसी पॉजिशन। इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। स्पोज़ यदि वह पब्लिक वर्कस को टच करते हैं तो उनके मोबाईल पर उससे संबंधित सभी कार्यों की लिस्ट आ जायेगी जो उनकी कांस्टीचुऐंसी में होगी। अब किसी एक

कार्य को इस लिस्ट में से टच करेंगे तो उस कार्य का स्टेटस आ जायेगा कि कब यह सैंक्शन हुआ, इसकी अभी फिजीकल और फाइनेंशियल प्रोग्रैस क्या है, विद फोटोग्राफ आ जायेगा। यह नहीं है कि अभी डिपार्टमैंट e-Constituency Management स्टार्ट करेंगे, तो अभी डिपार्टमैंट को यह भी एक काम करना पड़ेगा, वह काम डिपार्टमैंट पहले भी करते हैं। माननीय विधायकों की मंथली मीटिंग्ज़ होती हैं तो वहां पर डिपार्टमैंटस अपना पूरा स्टेटस एक हार्ड कॉपी के रूप में देते हैं। दूसरी मीटिंग होगी तो फिर वे पूरा उत्तर तैयार करेंगे तो बीच में जो लैग रहता है उससे अपडेटिड इंफोरमेशन नहीं रहती है। लेकिन इसमें जो भी इंफोरमेशन है वह अपडेट हो जाती है। इससे न केवल माननीय विधायक ही खुश हैं बल्कि जो अधिकारी हैं, डिपार्टमैंटस हैं, जो वहां के एच0ओ0डीज़0 हैं, उनको भी अपने मोबाईल पर यह पता लग रहा है कि मेरे डिपार्टमैंट के माननीय विधायक से रिलेटिड इतने काम हैं और यहां-यहां पर यह हो रहा है। जैसे कल माननीय अध्यक्षा, लोक सभा ने बताया कि हिमाचल की टोपोग्राफी दूर-दूर है, आपके यहां भी ऐसा होगा तो हर पंचायत में जाना माननीय विधायक के लिए सम्भव नहीं है। इसे वे अपने यहां मोबाईल पर देख सकते हैं। उसके बाद जहां उनको लगता है कि यहां कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ गलत हो सकता है तो वहां पर वे फिजीकली जाकर वैरीफाई कर सकते हैं या जब वहां जाते हैं तो वे लिस्ट मोबाईल पर खोलेंगे कि आपके यहां ये काम दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे दिखाओ। यह इंफोरमेशन वे पहले डिपार्टमैंट्स से मांगते थे, फिर क्वैश्चन पूछते थे, वह इंफोरमेशन ऑलरेडी उनके पास मोबाईल ऐप पर होगी और अच्छे ढंग से मोनिटरिंग हो सकती है। इसी तरह से जब एम0एल0ए0 डायरी को टच करते हैं तो उनको यह ऑप्शन दिखाई देती है कि किस तरह के पत्र उन्होंने भेजे हैं। इसमें कई टाइप्स रखी गई हैं। जो डिवैल्पमैंट से रिलेटिड वर्कस हैं, जब उस ऑप्शन को टच करेंगे तो वही लैटर्ज़ उनको दिखाई देंगे। ट्रांसफर से रिलेटिड दिखाई देंगे। डिस्क्रिशनरी ग्रांटस, एडवाइजरी, ग्रिवैंसिज़ इत्यादि टाइप्स रखी गई हैं। जब लैटर इसमें अपडेट होगा, तो ये टाइप्स सिलैक्ट करेंगे तो यह सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको क्लासीफाई कर देगा और यह अपने मोबाईल पर करना होता है। इसके बाद यह जान सकते हैं कि कितने पत्रों में अभी तक ऐक्शन पैंडिंग है और कितनों पर ऐक्शन हो चुका है और क्या हुआ है। इसमें वे यह भी जान सकते हैं कि कौन से पत्र जो 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 90 दिन से ज्यादा पैंडिंग हैं। जो भी लैटर आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विभागों को भेजे हैं वे आपके मोबाईल पर एक टच में उपलब्ध हैं। आप उनकी पूरी पैंडेंसी जान सकते हैं। ठीक है कि आप पांच या दस दिन से जो लैटर भेजे हैं उनको मोनिटर नहीं करना चाहते हैं लेकिन जिनको महीने से ऊपर हो

गया और उसमें डिपार्टमैंट ने कुछ नहीं किया है तो जब आप आवश्यकता अनुसार ऑप्शन को टच करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जायेगी और पूरा अपडेटिड स्टेटस रहेगा। सामने आप टी0वी0 स्क्रीन पर डिसप्ले पैनल में देख सकते हैं कि जब माननीय विधायक यह ऑप्शन टच करते हैं, जैसे आपको पहले पैरामीटर्ज़ बताए कि किस तरह का टाईप का है और कितने दिनों से पैंडिंग हैं, जब उसको टच करते हैं तो उतने लैटर्ज़ की लिस्ट मोबोइल में सामने आ जाती है। मैं उदाहरण सहित बताता हूं कि जैसे हमने अभी अपनी टी.वी. स्क्रीन पर कुछ पैरामीटर्ज़ सिलैक्ट किए, ये हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के चुनाव क्षेत्र का डेटा है इसी तरह से सभी 18 चुनाव क्षेत्रों में सभी के मोबाइल फोन पर इस तरह का डेटा है। जब इस पर टच करेंगें तो किसको भेजा, क्या सब्जैक्ट था और वहां पर क्या स्टेटस है, यह सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे आपने कोई लैटर दिया तो उसकी डिटेल इसमें आ जाएगी और अगर उसके साथ कुछ और अनैक्चर्ज़ हैं, उसकी हार्ड कॉपी डिपार्टमैंट को पहुंचा दी जाती है ।डिपार्टमैंट्स के कन्स्टिट्यूएंसी लैवल के जो भी अधिकारी नज़दीक होते हैं, उनको पहुंचा देते हैं ताकि वे इसको रीड कर सकें और आगे की कार्रवाई कर सकें । अभी तो हमने 15 दिन या महीने की बात की, महीने में भी कितने दिन का डिले है, 22 दिन का है, 23 दिन का हैं, इसमें हर चीज़ है । उसके बाद आप आगे देखें इसमें हम रिमार्क्स भर रहे हैं। जैसे विभाग का इस सम्बन्ध में कहना था कि स्कैनिंग की दिक्कत न रहे, जैसे आप वट्सऐप के अंदर टाइप कर देते हैं, उनको रिप्लाई आ जाता है तो उसको भी आप कंसीडर करें। तो आप देख सकते हैं कि नीचे उन्होंने रिमार्क्स में टाइप किया है। जो भी कम्युनिकेशन्ज़ कंस्टिट्युएंसी लैवल पर माननीय विधायक या अधिकारियों में होती है, आपको अगर कोई लीगल साइन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यह जानकारी चाहिए कि काम हुआ या नहीं हुआ , वह सारी आपके मोबाइल पर आ रही है लेकिन अगर लीगल लैटर है तो उसको भी अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन है। ऐसा लैटर जो उन्होंने आगे अपने किसी उच्च अधिकारी को भेजा है तो वे बता देंगें कि यह लैटर है, राइट बटन क्लिक करके पूरा साइन्ड लैटर यहां अटैच हो जाता है। इसके अलावा वैकेन्सी पोजीशन की रिक्वायरमैंट रहती है कि किस विभाग में क्या पोजीशन है, कितनी सैंक्शंड पोस्ट्स है और कितनी पोस्टें भर दी गई है, तो यह डेटा भी अपडेट किया जा रहा है। ये तीन इन्फोर्मेशन्ज़ अभी इनिशियल लैवल पर दी गई है । इसको अभी डिस्ट्रिक्ट लैवल तक कनैक्ट किया गया है । अगले चरण में मुख्य मंत्री जी,

माननीय मंत्री जी के साथ भी इसको कनैक्ट करेंगे और अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करुंगा, ये आगे इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : धर्मेश जी ने विषय रखा है, वैसे बड़ा छोटा सा विषय है, आप सभी के ध्यान में आ गया होगा। अगर दो-चार लाइनों में इसको प्रैक्टिकली कहना चाहें तो हम हर रोज़ कुछ चिट्ठियां लिखते हैं। हमने एक चिट्ठी एक्सिअन को लिखी, दूसरी पी.डब्ल्यू.डी. को, आई.पी.एच. को या बी.डी.ओ. को लिखी। एक हफ्ते बाद हम भूल जाते हैं कि हमने क्या लिखा था। एक महीने बाद हमारे पास सम्बन्धित व्यक्ति आता है कि मेरे काम का क्या हुआ तो हम कहते हैं कि हमने चिट्ठी लिख दी थी, हमें पता नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ, पता कराएंगें। जब यह चलता रहा, मैंने लगभग चार हजार चिट्ठियां लिखीं। गिनती का उत्तर आया, बाकी का उत्तर नहीं आया। काम हुआ या नहीं हुआ, हमें पता नहीं है । हमारे मुख्य मंत्री के कार्यालय में एक सी.एम. रैफ़निक करके एन.आई.सी. की डिवाइस है। उसके ऊपर उनको बैक रैफरैंस होता था कि ये पत्र आ रहे हैं, जा रहे हैं परन्तु वह काफी काम्प्लिकेटिड था। हम इसको सरल कैसे कर सकते हैं और हर विधायक के लिए इस डिवाइस को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए यह प्रयास किया गया है। अब जैसे आज मैंने अपने कार्यालय से 15 चिट्ठियां लिखी तो सभी चिट्ठियां हम इस ऐप पर लोड कर देते हैं और वे सीधी सम्बन्धित ऑफिसर के पास पहुंच जाती है। हम हार्ड कॉपी दें या न दें। एक हफ्ते या 15 दिन के बाद हम उससे यह अपेक्षा करते हैं कि उसके पास पोजिटिव या नेगेटिव; जो भी रिप्लाई है वह उसको हमारी ऐप के ऊपर डाल दे। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा, हमारे विधान सभा क्षेत्र में दस पूलों, दस सड़कों या दस पेयजल योजनाओं पर काम चल रहा है और उसके लिए 'ए' अमाऊंट सैंक्शन्ड है। उसमें कितना काम हो गया, उसके अनुसार उसकी प्रोग्रैस रिपोर्ट वह हर 15 दिन या एक महीने बाद अपलोड करे। मान लो, एक करोड़ रुपये की स्कीम थी जिसमें से 50 लाख रुपये खर्च हो गये और 50 लाख रुपये बाकी है। 'कोई हर्डल है या we are going smooth'; उसमें इस तरह की तीन-चार लाइन्स डाल देगा तो हम उससे अपडेट रहेंगे तथा जो उसमें एक बार डाल दिया वह उससे पीछे नहीं जा सकता। कल को वह यह नहीं बोल सकता कि साहब मैंने तो ऐसा बताया था क्योंकि ऐप में सब कुछ पहले आ चुका होता है। इस तरह से इसका बैनिफिट है और अगर हर विधायक इसको कर लेगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ी आसानी हो जायेगी। अभी हम ट्रायल के लिए कन्स्टिचुअंसी लैवल पर कर रहे हैं और फिर हम इसको मिनिस्ट्री लैवल तक जोड़ेंगे जिसका हमने स्कोप

रखा है। इसको जब मिनिस्ट्री से कनैक्ट करेंगे तो मंत्री के लिए जितनी चिट्ठियां लिखी जाती हैं उसका उत्तर भी उसके साथ आ जायेगा।

श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक (हरियाणा विधान सभा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या इसके लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सभी माननीय विधायकों को सरकार की ओर से लेटैस्ट टैक्नोलोजी और वैल ऐक्यूप्ड मोबाइल सैट प्रोवाइड करवाये गये हैं क्योंकि ज्यादातर एम0एल0एज0 ओर्डिनरी मोबाइल यूज़ करते हैं?

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : यह मोबाइल (अपना मोबाइल हाथ में लेकर दिखाते हुए कहा।) विधान सभा से प्रोवाइड करवाया गया है। इसमें वे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं जो हमें किसी भी अल्ट्रा मोडर्न कम्प्यूटर पर उपलब्ध होती है। यह सैमसंग का लेटैस्ट 'नोट-8' सैट है। इसमें कोई प्रोब्लम नहीं आती और इससे काम चल जाता है। इसके साथ प्रिन्टर भी दिया है यानि हर विधायक को 75-80 हजार रुपये का एक इक्विपमैंट दिया है।

श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक, हरियाणा विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा में विधायकों को लैपटोप और प्रिन्टर पहले से प्रोवाइड करवाये गये हैं। मैंने यह प्रश्न इसलिए किया है क्योंकि यहां पर ज्यादातर सूचना मोबाइल ऐप से रिलेटिड दी जा रही है। दूसरा, इसमें विधायकों की ई-कन्स्टिचुअंसी के बारे में बताया गया है और सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी विधायकों की अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार अपनी-अपनी रिक्वायरमैंट्स व डिमांड्स होती हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : आपका सवाल आ गया है और यह प्रश्न सत्ता पक्ष या विपक्ष का नहीं है। हमने पहली ट्रेनिंग विधान सभा अध्यक्ष के यहां दी, दूसरी मुख्य मंत्री के तथा तीसरी नेता प्रतिपक्ष के यहां दी। उनके इन्ट्रैस्ट को देखते हुए हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। माननीय वीरभद्र सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में ट्रेनिंग दे चुके हैं और यह सब के लिए हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक, हरियाणा विधान सभा : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ था और आपने उत्तर दे दिया। मेरा प्रश्न यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के कामों में बड़ा फर्क होता है। यह इतना ट्रांसपेरेंट है तो क्या सम्बंधित विधान सभा क्षेत्र की सारी-की-सारी सूचना पर्टिकुलर विधायक को ही प्राप्त होगी या उसको दूसरे लोग भी देख पायेंगे? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, हेड ऑफ दि

डिपार्टमैंट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट लैवल के हमारे दूसरे ऑफिसर्ज हैं; जिनके साथ हम कम्युनिकेशन्ज करते हैं। अगर उनकी ट्रांसफर हो जाती है तो क्या वे हमारे उस मोबाइल डेटा को अपने साथ ही ले जाते हैं या अपने स्थानांतरण के बाद उसको वहीं छोड़ जाते हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : अब मैं आपके लास्ट क्वैश्चन से शुरू करता हूं। हम हर कार्यालय को एक यूज़र आई0डी0 देते हैं और वह यूज़र आई0डी0 उस कार्यालय की होती है न कि उस ऑफिसर की होती है। ऑफिसर बदल गया मगर वह वैसे ही कन्टिन्यू रहेगा। दूसरी बात यह है कि मान लो जो मेरे नाहन निर्वाचन क्षेत्र की सूचना है वह मुझे ही मिलेगी, वह दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि उसके लिए यूज़र आई0डी0 अलग रखी गई है। इस तरह से हर विधान सभा क्षेत्र और हर कार्यालय के लिए यूज़र आई0डी0 अलग-अलग है। तीसरा, जो ऑफिसर होता है वह रूलिंग और अपोजिशन जरूर देखता है। यदि उसको लगता है कि इसके बारे में मुझे पूछा जाएगा तो वह जल्दी-से-जल्दी लोड कर देगा और यदि उससे नहीं पूछा जाएगा तो वह लोड नहीं करेगा। क्योंकि लोड करने में उसको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इस तरह से माननीय विधायक उसको अपने अनुसार ढाल सकता है। यह हर विधायक के लिए बराबर है।

डॉ0 निर्मल के0 सिंह, माननीय अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर, विधान सभाः कुछ लोग जो आई0टी0 की जानकारी रखते हैं यदि हम उनको आपके पास भेजें तो क्या उनके लिए वर्कशॉप या ट्रेनिंग का प्रावधान हो सकता है?

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : यदि आप वहीं पर ट्रेनिंग लेना चाहें तो हम वहीं पर ट्रेनिंग देने के लिए अपने लोगों को भेज देंगे।

डॉ0 निर्मल के0 सिंह, माननीय अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर विधान सभाः सर, ठीक है, धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : मैं अन्त में यह कहना चाहूंगा कि अभी हम इसमें विकास करने की प्रक्रिया में आगे चल रहे हैं। इसमें बहुत-सारी कमियां भी रहेगी और उसको समय के साथ-साथ दूर करने का प्रयास करेंगे।

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकारः ये नेवा (National e Vidhan Academy) का भी पार्ट होने वाला था और अभी हमने मना नहीं किया है। अगर नेवा का पार्ट-1 सैक्सैसफुल होता है तो Second Part में हम 5400 कांस्टिच्यूंसी क्रियट कर सकते हैं ताकि आपको केवल डॉटा एंट्री का पैसा ही देना पड़े और आप ट्रेनिंग करवाएं। हमने कोशिश की है कि नेवा (NeVA) का जो पार्ट-I है, वह हॉउस से रिलेटिड है। नेवा का जो पार्ट-II है, वह Constituency Management से संबंधित है, जैसा माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, हिमाचल प्रदेश बता रहे थे। लेकिन इसमें गवर्नेंस इश्यूज आएंगे। This is basically a governance issue. You give a question, he gives reply. But ultimately the MLAs are interested in getting the work done than a beautiful reply. तो इसमें आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे। इसलिए हम उस ओर नहीं जाना चाहते थे। क्योंकि भारत सरकार के लेवल पर Constituency Management करवाना is a huge task. सर, हमारी लोक सभा/राज्य सभा की कांस्टिच्यूंसीज अलग हैं और बाकी सबकी अलग-अलग हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : अल्टीमेटली ये तो आपको ही करना था।

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकारः सर, 900 करोड़ रुपये की एक सेन्टरली फंडिड स्कीम आ रही है। हम इसमें बड़े राज्यों के लिए 60 प्रतिशत् फण्ड देंगे और जो हिल्ज स्टेट्स हैं, उनको 90 प्रतिशत फण्डज़ देंगे तथा जो केन्द्र शासित प्रदेश हैं उनको 100 प्रतिशत फंडज देंगे। हम ये जो फंडिंग कर रहे हैं, इसमें हार्डवेयर के लिए 100 प्रतिशत, मैनपॉवर, 36 महीनों के लिए 20-30 प्रतिशत और बाकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जहां तक NeVA का कंसर्न है, इसमें सर्वर, एप्लीकेशन और मेंटेनेस इत्यादि पर जो 100 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा, वह भारत सरकार स्वयं वहन करेगी। इसमें राज्य सरकारों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये plug and play facility हम देंगे। नेवा वर्शन-II जिसमें कांस्टिच्यून्सी भी पार्ट होगा, उसको भी हम देने का प्रयास करेंगे लेकिन अभी हम ई-कांस्टिच्यून्सी के बारे में वायदा नहीं कर रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करने के पश्चात् इसके बारे में बता पाएंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल, सदस्य, विधान सभा, हरियाणा : क्या इसके लिए बजट पास हो गया है? क्योंकि फंडिंग उसके बाद ही की जा सकेगी। Where they have to make the representation क्योंकि हम इसको अपनी स्टेट में स्टार्ट करना चाहते हैं और हमें फंडिंग दे दें।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : मैडम, इसके लिए तो इन्होंने एप्लीकेशन्ज़ मंगवा ली हैं। आपके सचिव, हरियाणा विधान सभा ने भी भेज दी है।

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार: हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और कल आपके ऑफिसर्ज़ भी आ रहे हैं। यद्यपि, डॉटा एंट्री करने में आपका राज्य, हरियाणा आज बहुत आगे चल रहा है। पिछले कल की रात और आज में बहुत अंतर आया है। उन्होंने सारा डॉटा अपडेट कर दिया है। इसके अलावा पंजाब और तमिलनाडू ने भी अपना डॉटा अपडेट किया है। मैडम, आपकी जो कंरट इंफॉर्मेशन्ज हैं, हम उसी को अपडेट करवा रहे है।

श्री रणबीर सिंह पठानिया, सदस्य, जम्मू-कश्मीर विधान सभा : कश्मीर में ये असैंबली प्रोजेक्ट चलाया गया लेकिन वह ठीक से नहीं चला है। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आपके यहां से हमें बुलाएं या आपके यहां से लोग आएं ताकि इसको हम पूर्ण रूप से इन-एक्ट कर पाएं। आपने जैसे कहा है कि मैन पॉवर, हार्डवेयर या सर्वर किस तरीके से चलेंगे उसके लिए जम्मू-कश्मीर ने भी अप्लाई किया है। हमारे माननीय अध्यक्ष भी यहां हैं। We also put a very decent request before your goodself कि इसको जम्मू-कश्मीर में भी जल्दी-से-जल्दी इंप्लीमेंट किया जाये।

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार: मैं यहां माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर विधान सभा से अनुरोध करूंगा कि वे भी इस प्रकार की डायरैक्शन दें, जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, हि0 प्र0 सबको दबाव देकर काम करवाते हैं। सर, अगर आप एक डायरैक्शन देंगे तो आपके सारे अधिकारी इस काम को करेंगे और हमें

कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें तो विनम्रता दिखानी पड़ती है। We have to respect the cooperative federalism on all these issues. आपके अन्दर तो इनफॉर्मेशन एकत्र करवाने की अखण्ड क्षमता है। यहां पर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, वे हंस रहे हैं। लेकिन ये सब आपका पांच मिनट में आभार व्यक्त करेंगे और हमें यह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज ये दो दिन की कार्यशाला और सी0पी0ए0 कॉन्फ्रेंस समाप्ति की ओर अग्रसर है। हमें आप सबका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना है। आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया है। आपने अनेक प्रकार की असुविधाओं और मौसम की कठिन परीक्षा के बावजूद कार्यक्रम के हर पहलू में रूचि दिखाते हुए इसको कामयाब करने का प्रयास किया है। जो कमियां रही हैं, वे हमारी हैं और जो उपलब्धियां हैं, वे आपकी हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी चीज़ें इस दो दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से सीखने को मिली हैं और आप सबका सानिध्य मिला है। मैं सदैव इस सानिध्य के लिए आपका ऋणी और आभारी रहूंगा। आज श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, Minister of State for Parliamentary Affairs को इस सैशन की समाप्ति के लिए आना था। परन्तु आज प्रातः काल शिमला की फ्लाईट कैंसल होने के कारण वे नहीं आ पाये। ऐसे में हमने थोड़ी योजना भी बदली और ऊपर का सीटिंग प्लान भी बदला। मैं, हम में से वरिष्ठ साथी डॉ0 निर्मल के0 सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे सदन की समाप्ति पर अपनी बात कहें और समाप्ति की घोषणा करें। हम आगे पुनः इसी प्रकार और बेहतर फोर्म पर मिलें, इतना कह करके मैं माननीय निर्मल सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात कहें।

डॉ0 निर्मल के0 सिंह, माननीय अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर विधान सभाः अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉ0 राजीव बिन्दल, अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा, अध्यक्ष, गुजरात विधान सभा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा तथा सभी माननीय सदस्यगण व जितने भी अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं, साथियो, मैं भी एक दिन के लिए स्पीकर की कुर्सी पर बैठा था तो as a Speaker मेरा बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। क्योंकि जब स्पीकर बने तो उसके थोड़े समय बाद ही असैंबली सस्पैंडिड एनिमेशन में चली गई। जो अनुभव अन्य स्पीकर साहिबान का है, वह अनुभव मेरा नहीं है। हां, नीचे बैठ करके जरूर

डिप्टी सी0 एम0 होने के नाते मंत्रालयों को डील करने का मौका मिला है। लेकिन ये एक्सपोज़र मेरे लिए पहली बार है। माननीय अध्यक्ष महोदया, लोकसभा और अन्य विधान सभाओं के अध्यक्षों तथा बाकी माननीय सदस्यों के साथ बैठ करके जो इंटरेक्शन हुई है और नई टैक्नोलॉज़ी सीखने को मिली है। दुनिया की दौड़ आगे की ओर है यानि तरक्की की ओर है और इस दौड़ में हम किस तरीके से दुनिया के साथ अपना कदम-से-कदम मिला सकते हैं, ये यहां पर सीखने को मिला है। मैं विशेष तौर पर जम्मू-कश्मीर जैसे प्रदेश के बारे में कहूंगा कि वहां पर जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए पूरे देश में जो प्रयास हो रहा है, इससे मुझे और मेरे सभी साथियों को सीखने का मौका मिला है। यहां पर आपस में जो चर्चा हुई तो सभी को लग रहा है कि ये चर्चा बहुत अच्छी हुई है और इससे हमें एक अच्छा एक्सपोज़र मिला है। यहां पर जो NeVA, e-Vidhan और e-Constituency के बारे में बात हुई है, यह एक बहुत बड़ा कदम है। जैसा हमारा संकल्प है कि हमारे आम जनमानस को उनका हिस्सा मिले और उसमें जो विधान सभाओं का रोल है, उस रोल को और सुदृढ़ करने के लिए यह वर्कशॉप एक मील का पत्थर साबित होगी। यहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहां का मौसम बहुत ही सुहावना है। हमें यहां पर बहुत प्यार मिला और जैसा मेरे कश्मीरी साथी कह रहे थे कि यहां के लोग बहुत ही सरल हैं। हम यहां से अच्छी यादें लेकर वापिस जाएंगे। हमें आगे भी जब इस प्रकार का कोई अवसर मिलेगा तो हम उसका इंतजार करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल और यहां पर उपस्थित अपने सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : माननीय कंवर पाल जी काफी लम्बे समय से विधान सभा अध्यक्ष हैं। विधान सभा अध्यक्ष के रूप में इनका पांचवा वर्ष चल रहा है। आपने शायद सी.पी.ए. के सभी सम्मेलनों में भाग लिया है। आप सी.पी.ए. की कॉन्फ्रेंसिज में विदेश भी गए हैं। माननीय कंवर पाल जी आप भी दो शब्द इस सम्मेलन की समाप्ति पर कहें।

श्री कंवर पाल, माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा : हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, डा0 राजीव बिन्दल जी, विधान सभा अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, विधान सभा के अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष तथा इस कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी

विधायकगण एवं अधिकारीगण। इस कार्यशाला से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है इसके लिए मैं डा0 राजीव बिन्दल जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने हमारी बहुत अच्छी मेहमाननवाजी भी की है। आपने जो हमें e-Constituency की नई जानकारी दी है उससे हम सभी को बहुत लाभ होगा। माननीय मंत्रियों व विधायकों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के कई काम उनके कहने के बावूजूद भी बीच में ही अटके रहते हैं। निश्चित रूप से इस प्रणाली के अंतर्गत उन कार्यों को पूरा करने में गति मिलेगी। हम आपसे इसके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे क्योंकि इस प्रकार का विचार हमें सबसे पहले आपसे ही मिला है। जैसा कि माननीय निर्मल सिंह जी ने कहा कि यहां के लोग बहुत-ही सरल हैं और यह बात हम साथ बैठकर कर रहे थे। जैसे पंजाब में तो बहुत ज्यादा pomp and show होता है। हमारे हरियाणा में भी थोड़ा-थोड़ा pomp and show है। जो हमें आपसे सीखने को मिला उसे निश्चित तौर पर हम अमल में लाएंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : अब भाई राजेन्द्र जी (अध्यक्ष, गुजरात विधान सभा), अपनी बात कहेंगे।

श्री राजेन्द्र सुर्यप्रसाद त्रिवेदी, माननीय अध्यक्ष, गुजरात विधान सभा : आपने हिमाचल प्रदेश की वादियों में आने का मौका दिया है, गुजरात राज्य की तरफ से हम इस चीज के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी हास्पिटैलिटी भी बहुत बढ़िया रही है। हमें ऐसा लगा कि हम अपने प्रदेश में, अपने घर में ही है, शायद ही ऐसा लगा हो कि हम कहीं बाहर आए हैं। दो दिनों के अन्दर वर्षों जैसी मुलाकात हो गई। आदमी को हमेशा कुछ-न-कुछ सीखते रहना चाहिए। जो दो दिन का सम्मेलन हुआ अगर इसे में अपनी तरफ से नाम दूं, तो इसे मैं ई-महोत्सव कहूंगा। हमारा जो नया युग है इसमें हमें दुनिया के साथ कदम-से-कदम मिला करके चलना है। ई-महोत्सव में नेवा ने जो कदम बढ़ाया है, उसमें से पूरे प्रदेश की विधान सभाओं को कुछ-न-कुछ प्राप्त करना होगा। अध्यक्ष महोदय, हम आपका अभिवादन और अभिन्दन करते हैं कि हिमाचल प्रदेश ई-विधान के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। हमने निर्देश दिए हैं कि आपसे कुछ सीख करके हम गुजरात में भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगें। सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय बिट्ठल भाई जी यहां पर स्पीकर के तौर पर या अन्य पद पर रहे हैं।

Dr. Rajeev Bindal, Hon'ble Speaker, H.P. Vidhan Sabha : At that time it was called President. He was elected Chairman.

श्री राजेन्द्र सुर्यप्रसाद त्रिवेदी, माननीय अध्यक्ष, गुजरात विधान सभा : इस चीज को देखकर हमें बहुत आनंद हुआ। हम आपकी अनुमती से यहां फोटो जरूर खींचना चाहेंगे। क्योंकि आपकी अनुमति के बिना यहां पर किसी ने फोटो खीचीं है, उसके ऊपर केस चल पड़ा है। आपसे इसके लिए अनुमति मांगेंगे। आप सबसे मिल करके अच्छा लगा धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : आप सभी महत्वपूर्ण साथियों ने अपने उद्गार प्रस्तुत किए, शेष विधायक गण भी अपनी बात रखना चाहते होंगे । परंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसके तुरंत बाद होना है और मैं निमंत्रण भी आपको उसके लिए देना चाहूंगा, श्रद्धेय नरेन्द्र भाई मोदी जी दुनिया की सबसे बड़ी योजना "आयुष्मान भारत" की लाचिंग करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का कार्यक्रम 11ः 00 बजे आरम्भ हो चुका है। अभी 12ः 00 बजे आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी स्क्रीन पर सीधा आने वाले हैं। हम इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वहां पर चलेंगे जहां पर रात को हमने कार्यक्रम किया था, वहीं पर यह लाचिंग है। प्रदेश सरकार की तरफ से आप सब लोगों को निमंत्रण आया है, आप सभी वहां पर सादर आमंत्रित हैं। तत्पश्चात हमारे यहां विधान सभा परिसर में ही सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। उसके बाद जो घूमने के लिए जाने वाले हैं, हम सभी उनके साथ घुमने चलेंगे। जैसा भी आगे का कार्यक्रम आप लोगों का होगा कृपया अपना कार्यक्रम समयानुसार नोट करवा दें। अंत में आप सब का बहुत- बहुत धन्यवाद।

मैं आज अपने विधान सभा के सचिवालय का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने पिछले कई दिनों से लगातार एक-एक, छोटी-से-छोटी चीज को मोनिटर किया और जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश, और गुजरात सभी राज्यों के व्यक्ति अलग-अलग स्थानों पर ठहरे थे। कौन किसके साथ ठहरेगा कौन किसके साथ सम्पर्क करेगा। उन लोगों ने यह सारा कुछ कार्य देखा। ऐसे अपने सभी विधान सभा के साथियों को और हमारे सचिव, विधान सभा और विधान सभा की टीम को आज मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी लोक सभा अध्यक्ष, मैडम जी की अनुपस्थिति में मैं उनका एवं हमारे मुख्य मंत्री तथा अन्य सभी साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हूं।

इससे पहले की हम सम्मेलन को समाप्त करें, हम सभी वन्देमांतरम के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े होंगे।

(राष्ट्रीय गीत गाया गया)

*****